

India Inc not happy over World Bank's rankings

TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, OCTOBER 26

India Inc today said there have been significant changes on the ground in the ease of doing business which are insufficiently captured in the latest World Bank Doing Business rankings. In the World Bank's latest 'Doing Business' 2017 report, India's place remained unchanged from last year's original ranking of 130 among the 190 economies that were assessed on various parameters.

CII president Naushad Forbes said on the ground, there have been significant changes in ease of doing business which are insufficiently captured in the latest World Bank Doing Business rankings.

"The Doing Business report recognises India's reforms in key parameters, but measures the investment climate only in Delhi and Mumbai." Many

PM seeks report

■ Following the World Bank's latest Report on Ease of Doing Business which ranked India at 130, Prime Minister Narendra Modi has asked for a report from all concerned within a month about areas for improvement and asked the Cabinet Secretary to review the report thereafter

reforms that have taken place with the monitoring of DIPP at the state-level are not considered and do not reflect in the country-wise ranking," he said.

Assocham said though the government has made several path-breaking changes in legal framework and policy prescriptions like enactment of Goods and Services Tax, changes in insolvency law, liberalisation of FDI limits and rules in a host of sectors, the impact on the ground is generally visible after a lag.

विश्व बैंक की रैंकिंग से नाखुश उद्योग जगत

नई दिल्ली ■ वार्ता

विश्व बैंक के ड्रइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत को 130वां स्थान देने पर उद्योग जगत ने नाखुशी जताते हुए कहा कि देश में निवेश बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं लेकिन इस रिपोर्ट में उन्हें स्थान नहीं दिया गया है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष डॉ नोशाद फोर्ब्स ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, कारोबार को आसान बनाने के लिए देश में कई बड़े बदलाव किए गए हैं लेकिन विश्व बैंक की रिपोर्ट में इनपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। सरकार ने निवेश माहोल सुधारने के लिए छोटे उपक्रमों, श्रम नियमों, पर्यावरण अनुमतियों और कंपनियों के निबंधन समेत कई क्षेत्रों में अहम प्रयास किया है। डॉ फोर्ब्स ने कहा, इस साल का ड्रइंग बिजनेस रिपोर्ट एक जून तक की स्थिति के आधार पर तैयार किया

गया है। इसके कारण जीएसटी और इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जैसे महत्वपूर्ण सुधार इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा, ड्रइंग बिजनेस रिपोर्ट में कुछ अहम सुधारों को शामिल किया गया है लेकिन यह सिर्फ दिल्ली और मुंबई के निवेश माहोल पर आधारित है। औद्योगिक प्रवर्तन और संवर्धन विभाग की निगरानी में कई राज्यों में अहम सुधार हुए हैं जिसे इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

सीआईआई ने राज्यों की ओर से कारोबार को आसान करने पर जोर देते हुए उदाहरण के लिए बताया कि पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने नए निवेश प्रस्तावों के लिए तय सीमा के अंदर जरूरी मंजूरियां प्रदान करने का प्रावधान किया है। कई राज्यों ने भूमि अधिग्रहण, औद्योगिक क्लस्टर आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

द्योग संगठन फिक्की के अध्यक्ष

हर्षवर्धन नेवतिया ने प्रतिक्रिया में कहा, पिछले कुछ महीनों में विस्तृत सुधार किए गए हैं और इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ ही निवेश माहोल में भी सुधार हुआ है। कारोबार को आसान करना कारोबार की प्रतिस्पर्धिता के लिए अहम है और सरकार ने इसके मद्देनजर सही दिशा में कदम उठाए हैं। रैंकिंग बेहतर करने के लिए राज्यों को विशेष क्षेत्रों में सुधार तेज करने की जरूरत है। एसोचैम ने भी सरकारी प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, हालांकि सरकार ने कानूनी तंत्र और नीतिगत व्यवस्था में जीएसटी, इंसोल्वेंसी लॉ, एफडीआई लिमिट में उदारता आदि जैसे दूरगामी बदलाव किए हैं लेकिन जमीन पर इनका असर कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। संभवतः विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में अपेक्षित सुधार नहीं आ पाने की वजह यही रही होगी।

उद्योग जगत ने जताया विश्व बैंक की रिपोर्ट पर असंतोष

नई दिल्ली, (वार्ता),

लोकसत्य। विश्व बैंक के डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत को 130वां स्थान देने पर उद्योग जगत ने असंतोष जताते हुए कहा कि देश में निवेश बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाये गये हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में उन्हें स्थान नहीं दिया गया है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष डॉ. नौशाद फोर्ब्स ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कारोबार को आसान बनाने के लिए देश में कई बड़े बदलाव किये गये हैं, लेकिन विश्व बैंक की रिपोर्ट में इनपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। सरकार ने निवेश माहौल सुधारने के लिए छोटे उपक्रमों, श्रम नियमों, पर्यावरण अनुमतियों और कंपनियों के निबंधन समेत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं।

डॉ. फोर्ब्स ने कहा कि इस साल का डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एक जून तक की स्थिति के आधार पर तैयार किया गया है। इसके कारण जीएसटी और इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जैसे महत्वपूर्ण सुधार इसमें शामिल नहीं हो पाये हैं। उन्होंने कहा, कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सुधारों को शामिल किया गया है, लेकिन यह सिर्फ दिल्ली और मुंबई के निवेश माहौल पर आधारित है। औद्योगिक प्रवर्तन एवं संवर्धन विभाग की निगरानी में कई राज्यों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं जिसे इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। सीआईआई ने राज्यों द्वारा कारोबार को आसान करने पर ज़ोर देते हुए

उदाहरण के लिए बताया कि पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने नये निवेश प्रस्तावों के लिए तय सीमा के अंदर आवश्यक मंजूरियां प्रदान करने का प्रावधान किया है। कई राज्यों ने भूमि अधिग्रहण, औद्योगिक क्लस्टर आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उद्योग संगठन फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन नेवतिया ने प्रतिक्रिया में कहा कि पिछले कुछ महीनों में विस्तृत सुधार किये गये हैं और इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ ही निवेश माहौल में भी सुधार हुआ है। कारोबार को आसान करना कारोबार की प्रतिस्पर्धिता के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार ने इसके मद्देनजर सही दिशा में कदम उठाये हैं। रैंकिंग बेहतर करने के लिए राज्यों को विशेष क्षेत्रों में सुधार तेज करने की आवश्यकता है।

एसोचैम ने भी सरकारी प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हालांकि सरकार ने कानूनी तंत्र और नीतिगत व्यवस्था में जीएसटी, इंसोल्वेंसी लॉ, एफडीआई लिमिट में उदारता आदि जैसे दूरगामी बदलाव किये हैं, लेकिन जमीन पर इनका असर कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। संभवतः विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में अपेक्षित सुधार नहीं आ पाने की वजह यही रही होगी। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक ने संशोधित अनुमान में वर्ष 2016 के लिए कारोबार आसान करने तथा बेहतर निवेश माहौल के रैंकिंग में भारत को 130वां स्थान मिला है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कारोबार की आसानी तथा बेहतर निवेश माहौल पर आधारित होती है। इससे पहले भारत 131वें स्थान पर था।

डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सुधारों को शामिल किया गया है, लेकिन यह सिर्फ दिल्ली और मुंबई के निवेश माहौल पर आधारित है